दैनिक भास्कर

दैनिक भास्कर, भोपाल, शनिवार, 30 मार्च, 2024 06

पिन पॉइंट ग्रोथ को चाहिए रिसर्च, इनोवेशन

समृद्धि के लिए क्वालिटी यूनिवर्सिटी सिस्टम जरूरी

अनिल अग्रवाल
चेयरमैन, वेदांता समूह

किसी भी देश की समृद्धि एक हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि वहां के यूनिवर्सिटी सिस्टम की क्वालिटी कैसी है। भारत की सबसे बड़ी संपत्ति 130 करोड़ लोग हैं। हर तीन में से एक भारतीय 18 साल से कम उम्र का है। यदि वैश्विक मानकों की किफायती यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक इनकी पहुंच हो, तो उन्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इससे दुनिया की अग्रणी इकोनॉमी के तौर पर भारत का निरंतर विकास सुनिश्चित हो सकता है। देश में उच्च शिक्षा के कई विश्व स्तरीय संस्थान हैं। आईआईटी जैसे कई हायर स्टडी इंस्टीट्यूशन दुनिया के टॉप-500 यूनिवर्सिटी में शामिल होते रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, दिल्ली यूनिवर्सिटी और अन्ना यूनिवर्सिटी

भारतीय छात्र विदेश में पढ़ाई पर इस साल करीब 64,000 करोड़ खर्च करेंगे। हमें ये पैसा बचाने की रणनीति पर काम करना चाहिए।

जैसे मुट्ठीभर शिक्षा संस्थान क्यूएस और टाइम्स ऑफ लंदन की ग्लोबल रैंकिंग में भी शामिल हुए हैं। हालांकि, दुनिया के टॉप-50 में कोई भी भारतीय यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। हाल ही में 5 यूनिवर्सिटी के साथ चीन ने वर्ल्ड टॉप-50 में प्रवेश किया है। ये बड़ी आर्थिक शक्ति के तौर पर चीन की उभरती स्थिति से मेल खाता है। भारत को भी दुनिया के टॉप-50 में शामिल यूनिवर्सिटी की जरूरत है। इसे और बहुत सारे अच्छे शिक्षा संस्थान चाहिए, जो टॉप-500 में शामिल हों। हमें क्वालिटी और मात्रा, दोनों की जरूरत है।

हाल के वर्षों में विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीय छात्र काफी बढ़े हैं। फिलहाल करीब 8 लाख भारतीय छात्र दुनियाभर की यूनिवर्सिटीज और शैक्षणिक संस्थानों की डिग्री ले रहे हैं। ये ट्रेंड भारतीय छात्रों की बढ़ती आकांक्षाओं का प्रतीक है। हालांकि, विदेशों में पढ़ने वाले भारतीय छात्र ट्यूशन फीस और रहने-खाने पर बड़ी रकम खर्च करते हैं। विदेश में भारतीय छात्र अकेले ट्यूशन फीस पर सालाना 16-48 लाख रुपए खर्च करता है। ये पढ़ाई की जगह और पाठ्यक्रम पर निर्भर करता है। रहने-खाने, यूनिवर्सिटी तक आने-जाने और हेल्थकेयर जैसे अतिरिक्त लागत शामिल करने पर कुल सालाना खर्च 56-64 लाख तक जा सकता है। अधिकांश भारतीयों के लिए ये खर्च उठाना मुमकिन नहीं है। यह देश के लिए भी महंगा है। एक अनुमान के मुताबिक, भारतीय छात्र (या उनके माता-पिता) 2024 में 64,000 करोड़ रुपए तक खर्च करेंगे। भारत में वैश्विक ख्याति के ज्यादा संस्थान बनाकर ये पैसा बचाया जा सकता है, जो घरेलू अर्थव्यवस्था को सहारा देगा।

ऐसा नहीं है कि भारत में हमेशा से वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी की कमी रही है। देश के पास उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों की समृद्ध विरासत है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना ऑक्सफोर्ड से 600 साल पहले की गई थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय तो और भी पुराना है। ये उत्कृष्ट शिक्षा के वैश्विक केंद्र थे, जिन्होंने दुनियाभर के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों और छात्रों को आकर्षित किया। ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम ये ख्याति दोबारा हासिल कर न सकें। सरकार की भूमिका हमेशा रहेगी, लेकिन उसकी प्राथमिकताएं प्रतिस्पर्धी रहेंगी। देश में अभी हायर एजुकेशन के मुकाबले स्कूली शिक्षा, पोषण और बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल जैसी जरूरतें कहीं ज्यादा हैं।

वैश्विक स्तर पर उच्च शिक्षा के कुछ सबसे अच्छे संस्थान परोपकारियों ने स्थापित किए गए हैं। उनका विस्तार आर्ट, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, कानून, मैनेजमेंट जैसे पाठ्यक्रमों तक सीमित नहीं है, बल्कि बुनियादी ढांचा भी इसमें शामिल है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड 8,000 हेक्टेयर में फैला है। बोस्टन का पूरा शहर हार्वर्ड और एमआईटी समेत कई यूनिवर्सिटी के साथ ग्लोबल एजुकेशन हब बन गया है, जो दुनिया के टॉप-5 में शामिल हैं। ऐसे ग्लोबल हब रिसर्च और इनोवेशन के जरिये इंडस्ट्री ग्रोथ भी आसान बनाते हैं। भारत में विज्ञान और टेक्नोलॉजी का ठोस आधार है। हमारे पास जबरदस्त उद्यमी हैं। समाज और अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों और बिजनेस के साथ मिलकर काम करने की बहुत गुंजाइश है। विश्वविद्यालयों में निजी पहल को फलने-फूलने के लिए सरकार को उच्च शिक्षा क्षेत्र को सरकारी बंधन से मुक्त करना होगा। हां सरकार फैसलिटेटर की भूमिका निभा सकती है, जैसा कि अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में कर रही है। आलोचक अक्सर कहते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी का इकोसिस्टम भले ही परोपकारी हों और उनका फोकस प्रॉफिट न हो, लेकिन यह आम लोगों की पहुंच से बाहर हो सकता है। इसका समाधान इस सरल सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए कि यदि कोई छात्र मेधावी है और किसी खास यूनिवर्सिटी या कोर्स के लिए जरूरी अंक प्राप्त करता है, तो उसे पैसे की कमी के कारण मौके से वंचित नहीं किया जा सकता। प्राइवेट यूनिवर्सिटी और सरकार मिलकर एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं, जिसमें सभी मेधावी छात्रों को पर्याप्त वित्तीय सहायता मिले।

बहरहाल भारत के आर्थिक विकास के लिए हालात अनुकूल हैं। यदि हम इसका लाभ उठाकर उच्च शिक्षा प्रणाली में निवेश कर सकें और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाएं तो पहले से ही तेज विकास दर को और रफ्तार दे पाएंगे। युवाओं को रोजगार पाने और देश को गौरवशाली भविष्य की दिशा में ले जाने के लिए सशक्त भी बना पाएंगे।